क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान

जयपुर (विसं)। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश में नॉन-पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने बताया कि देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 6 सडकों के नवीनीकरण और 15 पुलियाओं की मरम्मत के लिए 17.15 करोड रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 2 सडक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 4 कार्य प्रगति पर हैं। वर्षा और अन्य कारणों से क्षितग्रस्त सड़कों का भी प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण प्रस्तावित है।मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि देवली-उनियारा क्षेत्र में कुल 52 पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनमें से 15 कार्य स्वीकृत किए गए।

इनमें 1 कार्य पूर्ण, 12 प्रगतिरत हैं। शेष 2 कार्यों स्टेट हाईवे-29 से अनवार नगर तथा गुराई से जेल रोड में से एक कार्य को निरस्त कर राशि को दूसरे कार्य में समायोजित करने की अनुशंसा की गई है।

'गौवंश के लिए 25 प्रतिशत बढ़ाया अनुदान'

जयपुर (विसं)। गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं एवं नन्दीशालाओं को नियमित रूप से अनुदान उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार ने अनुदान राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके बाद भी नियमानुसार राशि में वृद्धि की गई है। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरलाल सहारण के पूरक प्रश्नों के जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 9 व नन्दीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित गौवंश के लिए 12 माह सहायता राशि दी जा रही है। इससे पहले मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि चूरू में 278 गौशालाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 (संशोधित 2021) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से पात्र गौशालाओं में गौवंश को चारा-पानी एवं पशु आहार के लिए 270 दिवस सहायता राशि दो चरणों में दी जाती है। वर्तमान में बड़े गौवंश के लिए 50 रुपये तथा छोटे गौवंश के लिए 25 रुपये प्रतिदिन सहायता दी जा रही है। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि विभाग की अन्य योजनाओं के तहत भी पात्र गौशालाओं को आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है।

हड़ताल के तीसरे दिन उग्र हुआ बस ऑपरेटरों का आक्रोश

दौसा के महुआ में प्रदर्शनकारियों ने बस ड्राईवर को नीचे उतारकर जूतों की माला पहनाई, तो बीकानेर में परीक्षा केन्द्र नहीं पहुंचने पर छात्राओं के आंसू छलके

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं होने के कारण बस ऑपरेटरों का धैर्य जवाब दे रहा है और अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण से उग्र रूप अख्तियार करने लगा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में करीब 35 हजार बसों के पहिए थमे रहने से आम जनता, परीक्षार्थी और फाल्गुन मेले में जा रहे श्रद्धालु बेहाल है।

वहीं जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर गुरुवार को प्रदर्शन का हिंसक चेहरा सामने आया। हड़ताली ऑपरेटर्स ने जबरन निजी बसें रुकवाई और नियमों की अवहेलना कर बस चलाने वाले चालक-परिचालकों के साथ धक्का-मुक्की की। दौसा के महुआ में प्रदर्शनकारियों ने एक बस कंडक्टर को जबरन नीचे उतारकर जूतों की माला पहना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

अलवर में भी ऑपरेटरों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

राजधानी जयपुर में निजी बस ऑपरेटर्स ने गुरूवार को नारेबाजी कर विरोध जताया।

इधर खाटू श्याम जी का लक्खी फाल्गुन मेला चल रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसों की अनुपलब्धता के कारण श्रद्धालुओं को भारी असुविधा हो रही है। दूसरी ओर, होली का पर्व नजदीक होने के कारण घर जाने वाले प्रवासी श्रमिक और यात्री बस अड्डों पर फंसे हुए हैं। बीकानेर के नापासर में हृदयविदारक स्थिति दिखी, जहां परीक्षा केंद्र जाने के लिए साधन न मिलने पर छात्राएं सड़क पर ही फूट-फूटकर रोने लगीं।

ऑल राजस्थान कांटेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव का कहना है कि वे संवाद के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी ने असंतोष पैदा कर दिया है।

- **सरकार की चुप्पी से लगातार बढ़ रहा है गतिरोध, 35 हजार बसों के पहिए थमने से प्रदेश में हाहाकार**

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं,हडताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस हडताल से न केवल जनता परेशान है, बल्कि सरकार को भी टोल और डीजल वैट के रूप में करोडों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

बस संगठनों का आरोप है कि सरकार वार्ता के बजाय प्रशासनिक दबाव से आंदोलन को कुचलना चाहती है। ऑपरेटरों के अनुसार यह व्यवसाय हजारों परिवारों का आधार है, जिन पर अब संकट मंडरा रहा है।

सदन के गतिरोध पर कांग्रेस की रणनीतिक बैठक आज

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार सुबह आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 10:15 बजे की विपक्ष लॉबी में होगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। सदन में हाल ही में उपजे गतिरोध और लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल सरकार की कार्यशैली, सदन में विपक्ष को बोलने का अवसर न मिलने और विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं होने जैसे विषयों पर अपनी रणनीति तय करेगा। सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह भी विचार किया जाएगा कि आगामी कार्यवाही के दौरान कांग्रेस किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति अपनाए। विपक्ष राज्य में कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने सभी विधायकों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि एकजुटता का संदेश दिया जा सके। बैठक में सदन के भीतर और बाहर आंदोलन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।

'पारंपरिक उपचार पद्धितयाँ सिर्फ आस्था नहीं, भविष्य की उम्मीद'

हरिद्वार (कासं)। पतंजलि अनुसन्धान संस्थान और पतंजलि विश्विद्यालय की ओर से गुरूवार को 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "प्लांट्स टू पेशेंट्स सीरीज 4- एथनोफॉर्मोकोलॉजी बियोंड टाइम्स" पूर्ण हुआ। सम्मेलन से विश्व को संदेश दिया गया कि, पारंपरिक उपचार पद्धितयाँ केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाण के माध्यम से भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का सशक्त आधार बन सकती है।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेरूजिया विश्वविद्यालय, इटली और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलोजी के प्रेजिडेंट, प्रोफेसर डोमेनिको विटोरियो डेलफिनो, कोट दअज़ूर विश्वविद्यालय, फ्रांस से प्रोफेसर लुई-फेलिक्स नॉटियस, ग्राज विश्विद्यालय, आस्ट्रिया से प्रोफेसर रुडोल्फ बाउर, नीदरलैंड्स से एल्सेवियर प्रकाशन की सीनियर पब्लिशर, प्रोफेसर ऐन मैरी शोनी-पोरडॉन, माए फ़ा लुआंग विश्विद्यालय, थाईलैंड से प्रोफेसर तिडारैट डुआंग्योट, सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलोजी के संस्थापक पुलक के. मुखर्जी, एम्स, कल्याणी से प्रोफेसर वाई. के. गुप्ता, एम्स, ऋषिकेश की प्रोफेसर मीनू सिंह और उनके साथ प्रोफेसर पुनीत धामिजा, , नई दिल्ली से प्रोफेसर (मेजर) एम. डी. रे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्रोफेसर विक्रम गोटा, एवं प्रोफेसर संजय जाचक शरीक हुए।

इन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के समन्वय पर मंथन किया।

स्वामी रामदेव ने कहा कि शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान और वैदिक सनातन ज्ञान का संगम ही भविष्य की चिकित्सा पद्धित की दिशा सुनिश्चित कर सकता है। हजारों वर्षों से संरक्षित भारतीय चिकित्सा ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है और पतंजलि एक वैश्विक केंद्र के रूप में प्रमाण-आधारित भारतीय चिकित्सा को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि विश्वभर में आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धित के साथ ही यूनानी, मिस्त्र, ग्रीक, तिब्बती, चीनी, जापानी, कोरियाई चिकित्सा पद्धित विद्यमान है, आवश्यकता है इन चिकित्सा पद्धितयों को शोध और साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने की, जिससे एक होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल और ग्लोबल हेल्थ का एक सशक्त माध्यम बन सके जिससे जनमानस को रोगों के लिए एक सुगम, सुरक्षित, सुलभ समाधान मिले।

पतंजलि के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि जब प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है।

विधानसभा में गूंजा निजी बसों की हड़ताल का मुद्दा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बीते 3 दिन से चल रही प्राइवेट बसों की हड़ताल का मामला गुरूवार को विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला और निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने शून्यकाल में सरकार से आग्रह किया कि हड़ताल तत्काल खत्म करवाई जाए। चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि हड़ताल के कारण यात्री, विशेषकर खाटू श्यामजी जाने वाले लोग परेशान हैं। सामान्य दिनों में 35 हजार प्राइवेट बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल केवल 33 प्रतिशत ही बसें ही चल रही हैं। आक्या ने यह भी कहा कि छोटी गाड़ियों पर अवैध तरीके से चालान लगाया जा रहा है, जिससे आम लोग शोषित हो रहे हैं।कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हड़ताल से रोजगार प्रभावित हुआ है। करीब 35 हजार बसों की हड़ताल के कारण 3.50 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। होली का त्यौहार आने वाला है और मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे।

बराला ने खाटूश्यामजी मेले में दूसरे राज्यों से आए हजारों लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए कहा कि टैक्सी वाले भी 70 किलोमीटर के लिए 7000 रुपए ले रहे हैं। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता पर जो बोझ है वह सरकार की अकर्मण्यता का परिणाम है।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए बस ऑपरेटर्स से चुपचाप संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक वार्ता नहीं हो रही। पहले 23 मांगें थीं, फिर 14 और अब 9 मांगों पर वार्ता हो रही है। बराला ने कहा कि हड़ताल के मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मांगों में "वन इंडिया वन टैक्स" शामिल है। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार "वन नेशन, वन इलेक्शन" और "वन नेशन, वन आधार" जैसी नीतियों की बात कर सकती है, तो आम लोगों को अधिकार देने की बात क्यों नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बदल रहा औद्योगिक परिदृश्य

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को निवेश एवं उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत संरचनाएं, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न नवाचारों से राजस्थान को देश में उद्योग का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसी क्रम में सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाई जाएगी। इस नीति का मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदन किया गया है। इस नीति से राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही, इससे निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी सुनिश्चित होगा।

- **राज्य सरकार जल्द ही औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाएगी**

इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार विकास मॉडल निर्धारित किए गए हैं। मॉडल-ए के तहत पूर्णत: रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास किया जाएगा। वहीं, मॉडल-बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण की जाएगी एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगी। इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा।

नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। इस नीति के अंतर्गत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ तक के पार्क हेतु 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ हेतु 30 करोड़ तथा 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु 40 करोड़ रुपए होगी। इस नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा तथा औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा, इस हेतु सीईटीपी पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क) का प्रावधान किया गया है।

दुल्हन सौदेबाजी गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस की सीआईडी अपराध शाखा विंग ने दुल्हन बेचने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट के खिलाफ अपना शिकंजा करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना भंवरलाल शर्मा की गिरफ्तारी के ठीक बाद सीआईडी टीम ने एक और कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी महावीर सुथार को जयपुर के मानसरोवर स्थित भारत माता सर्किल से दस्तयाब कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर बालोतरा पुलिस की ओर से दस हजार रुपये का इनाम घोषित है।

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बिपिन कुमार पाण्डेय के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में गठित टीम के प्रभारी एसआई शैलेन्द्र शर्मा व सदस्य कांस्टेबल बृजेश शर्मा को सूचना मिली थी कि इस गैंग का सक्रिय सदस्य महावीर निवासी उनियारा टोंक जयपुर के मानसरोवर इलाके में छिपा है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत माता सर्किल पर जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया।।

पशुधन बीमा योजना को लेकर विधानसभा में घमासान मचा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुधन बीमा योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पर पशुपालन मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और देखते ही देखते मामला तीखी नोकझोंक में बदल गया। आरोप-प्रत्यारोप और तंज कसने के बीच सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

पूरक प्रश्न के दौरान हरीश चौधरी ने कहा कि पशुपालन मंत्री सीधे-साधे और सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाड़मेर में गैर संवैधानिक पावर सेंटर उन्हें काम नहीं करने देते और पाली में भी दबाव की स्थिति रहती है। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री है, वहां पर गैर सवैधानिक ताकते काम नही करने देते हैं। पाली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ काम नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन सीधे-साधे मंत्री को संरक्षण दिया जाना चाहिए।

हरीश चौधरी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे गलत बताते हुए विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी संस्कृति का परिचय दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि हरीश चौधरी को मंत्री पद से क्यों हटाया गया था।

- **42 लाख के लक्ष्य पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव**

हरीश चौधरी ने कहा कि उनके मूल सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा कि राजस्थान में बीमा कंपनियों को कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने पशुपालकों को वास्तविक लाभ मिला है।

इस पर मंत्री जोराराम कुमावत ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत दो दुधारू गाय-भैंस का बीमा करने की घोषणा हुई। महंगाई राहत शिविरों में करीब 1 करोड़ 10 लाख पशुपालकों से आवेदन लिए गए, लेकिन सिर्फ 1764 पशुओं का बीमा किया गया। 23 क्लेम दावे प्राप्त हुए, जिनमें से एक भी भुगतान पशुपालकों को नहीं हुआ।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के आने के बाद 7 लाख 33 हजार रुपए का भुगतान किया गया और अब व्यापक स्तर पर योजना को लागू किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 31 लाख 10 हजार 735 पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है और 16 लाख से अधिक पशुपालकों को पॉलिसी जारी कर दी गई है। शेष पशुओं का बीमा भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च तक 42 लाख का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि अब केवल एक महीना शेष है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने कम समय में शेष लाखों पशुओं का बीमा कैसे किया जाएगा?

बहस के दौरान सरकारी मुख्य सचेतक भी बीच में बोलने लगे। जूली ने ऊंची आवाज में जवाब मांगा तो गर्ग ने कांग्रेस पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में विनम्रता रखनी चाहिए, मंत्री किसी के गुलाम नहीं हैं। हंगामे की स्थिति बनती देख स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया और माहौल को शांत करने की कोशिश की। हालांकि पशुधन बीमा योजना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आंकड़ों और दावों की जंग जारी रही।

विधानसभा में डोटासरा-दिलावर और जोगाराम पटेल के बीच तीखी नोकझोंक

तीनों नेताओं के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर शुरू हुई बहस जब निजी आरोपों व टिप्पणियों पर जा पहुंची तो देखते ही देखते सदन का माहौल अखाड़े जैसा बन गया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के समय सदन अखाड़ा बन गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सत्ता पक्ष के मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके चलते सदन में कई बार हंगामे की स्थिति पैदा हुई। डोटासरा ने जहाँ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं मंत्रियों ने उनके कार्यकाल के पुराने मामलों को लेकर पलटवार किया।

बहस की शुरुआत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एसआईआर में अपनी पसंद की लिस्ट न आने के कारण पुराने ढर्रे पर चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यहाँ बेईमानी नहीं कर सकी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि डोटासरा को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है और आगामी निकाय व पंचायत चुनावों में भाजपा का ही परचम लहराएगा।

- **सदन में व्यक्तिगत हमलों का दौर तब शुरू हुआ जब जोगाराम पटेल ने बिड़ला ऑडिटोरियम के घटनाक्रम का जिक्र किया। इस पर डोटासरा ने तल्ख लहजे में कहा कि "मेरा नाम गोविंद डोटासरा है, सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी भुला दूंगा।"**
- **जवाबी हमले में मंत्री पटेल ने भी कहा कि चौकड़ी भुलाना हमें भी आता है।" इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 2000 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाले का फंदा आ रहा है। डोटासरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे किसी भी जांच का स्वागत करते हैं।**

सदन में व्यक्तिगत हमलों का दौर तब शुरू हुआ जब जोगाराम पटेल ने बिड़ला ऑडिटोरियम के घटनाक्रम का जिक्र किया। इस पर डोटासरा ने तल्ख लहजे में कहा कि "मेरा नाम गोविंद डोटासरा है, सांस भी निकाल लिया तो चौकड़ी भुला दूंगा।" जवाबी हमले में मंत्री पटेल ने भी कहा कि चौकड़ी भुलाना हमें भी आता है।" इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 2000 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाले का फंदा आ रहा है। डोटासरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। उन्होंने दिलावर पर हमला बोलते हुए दावा किया कि मंत्री पर 14 केस दर्ज हैं और वे 6 मामलों में जमानत पर बाहर हैं, वरना सलाखों के पीछे होते। दिलावर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की लोकप्रियता से डरती है, इसलिए मदन दिलावर को उनके पीछे लगा रखा है। उन्होंने डॉ. किरोड़ी को अपना साढू बताते हुए उनके प्रति सहानुभूति जताई। इसके जवाब में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हमने आरएसएस की शाखा में राष्ट्रभक्ति सीखी है। हमारा लक्ष्य पद नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना है। हम पदों के पीछे नहीं भागते।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार मजदूर और किसान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर किसानों के हितों के साथ समझौता कर रही है। जूली ने चेतावनी दी कि सत्ता और बहुमत हमेशा नहीं रहता और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।

स्पीकर देवनानी ने श्रवण कुमार को बोलने से रोका तो विपक्ष ने किया सदन की कार्यवाही का बहिष्कार

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बोलने की मंजूरी रद्द करने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा।

सभापति ने पहले श्रवण कुमार को बोलने की अनुमति दे दी, इसके बाद वे अनुदान मांगों पर बोलने लगे। इसी बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन में आए और श्रवण कुमार को बोलने से रोकते हुए कहा कि, "मैंने पहले ही आपको आज मना किया था, आप 6 दिन से बोल रहे हैं, आपको बाद में बोलने की अनुमति दे देंगे, लेकिन आज नहीं। मैं अपने आदेशों की अवहेलना सहन नहीं करूंगा।"

- **विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही देर शाम आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई**
- **नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि "अनुमति देकर कांग्रेस के सदस्य की बेइज्जती की गई, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"**

इस घटना के बाद अनुदान मांगों पर बहस जारी रही। डग विधायक कालूराम बोल रहे थे, तभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए श्रवण कुमार के बोलने की अनुमति वापस लेने को गलत बताते हुए विधायक का अपमान बताया। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई। जूली ने कहा कि हम आप लोगों की मेहरबानी से नहीं है। अनुमति देकर सदस्य की बेइज्जती की गई, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह से ही दादागिरी से ही हाउस चलाना है तो चला लीजिए, यह तरीका नहीं होता। इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई।

शाम को 7:27 पर विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर अनुदान मांगों पर बहस आगे बर। नाराज कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके चले गए।

6 मार्च तक कामकाज तय

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में 6 मार्च तक का कामकाज तय किया गया है। विधानसभा में 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद 5 मार्च को विधानसभा में जन विश्वास विधेयक और राजस्थान दुकान और वाणिज्य संशोधन बिल बहस के बाद पारित होंगे, 6 मार्च को डिस्टर्ब एरिया बिल पारित होगा।

हालांकि 2 से ज्यादा बच्चों वालों को पंचायतीराज और निकाय चुनाव लड़ने की बाध्यता हटाने वाले दो बिलों के पास होने का समय अभी तय नहीं हुआ है। बुधवार को ही कैबिनेट ने दोनों बिलों को मंजूरी दी थी।